

(2010) 13 (एडीडीएल.) एस. सी. आर. 820

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली

बनाम

मसर्स हरि चंद श्री गोपाल और अन्य

(2004 की दीवानी अपील संख्या-1878-1880)

18 नवंबर, 2010

[एस. एच. कपाडिया, सी.जे.आई., बी. सुदर्शन रेड्डी, के. एस. पैनिकर राधाकृष्णन, सुरिंदर सिंह निजार और स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्तिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944:

अध्याय X-आरआर.192, 174 - अंतिम उत्पादों (चबाने वाले तंबाकू) के निर्माण के लिए विशिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं (किमाम) का आकर्षक रूप से उपभोग करने वाला निर्धारिती-अधिसूचना संख्या 121194-सी. ई. दिनांक 11.8.1994 के अनुसार निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं (किमाम) पर उत्पाद शुल्क की छूट-प्राप्तकर्ता के अंत में अभिलेखों के आधार पर अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के 'इच्छित उपयोग' और 'पर्याप्त अनुपालन' के आधार पर दावा किया गया-माना गया: आपूर्तिकर्ता पक्ष की ओर से कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नियम 174 के तहत प्राप्त किए गए और न ही अभिलेख रखे गए-आवेदक की ओर से, प्राप्तकर्ता की ओर से, वैधानिक प्रपत्रों में विभिन्न घोषणाएं देने में विफलता ताकि छूट का दावा किया जा सके-अध्याय X में विभिन्न नियमों के तहत गणना की गई शर्तों का पालन न करना और अध्याय X के तहत निर्धारित विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों का पालन न करना-इस प्रकार, 'इच्छित उपयोग' और 'पर्याप्त अनुपालन' की याचिका स्थापित नहीं हुई-न्यायाधिकरण द्वारा

पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985-अधिसूचना संख्या 121194-सीई दिनांक 11.8.1994 - 'पर्याप्त अनुपालन' और 'इच्छित उपयोग' का सिद्धांत।

अध्याय X-पंप के पुर्जों और गन मेटल कास्टिंग का निर्माण और गुप्त निष्कासन-अधिसूचना संख्या 312001-सी. ई. और 612001-सी. ई. के अनुसार उत्पाद शुल्क और जुर्माने के भुगतान से छूट-न्यायाधिकरण द्वारा अनुदान, भले ही अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया हो, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन केवल प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा माल की प्राप्ति और उनके उपयोग को स्थापित करने के लिए किया जाना है। टिकाऊ नहीं-न्यायाधिकरण ने अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के उद्देश्य और उद्देश्य की पूरी तरह से अनदेखी की-आपूर्तिकर्ता की ओर से निर्मित वस्तुएं उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं थीं और यदि कोई पक्ष शुल्क में छूट चाहता है, तो उसे कुछ पूर्व-आवश्यकताओं का पालन करना था-उद्देश्य यह देखना था कि छूट अधिसूचना की आड़ में माल को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट या उपयोग नहीं किया जाना चाहिए-इस प्रकार, "पर्याप्त अनुपालन" और सी "इच्छित उपयोग" की याचिका खारिज कर दी जाती है-न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-अधिसूचना संख्या 312001-सीई और 612001-सीई-"पर्याप्त अनुपालन" और "इच्छित उपयोग" का सिद्धांत।

अध्याय X-निर्धारिती विनिर्माण और समाशोधन मुद्रित परिपथ बोर्ड-अधिसूचना संख्या 48194-सीई दिनांक 01.03.1994 के अनुसार उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट। - दावा-आयोजित-अनुज्ञेय नहीं-निर्धारिती ने अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया-यह शुल्क से छूट का दावा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा-

इस प्रकार, न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985-अधिसूचना संख्या 48194-सीई दिनांक 1.3.1994।

विधानों की व्याख्या-छूट खंड-का निर्माण-समझाया गया

सिद्धांत/सिद्धांत-'पर्याप्त अनुपालन' और 'इच्छित उपयोग' का सिद्धांत-समझाया गया।

निर्धारित-प्रतिवादी, सिविल अपील संख्या 1878-1880 में, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए थे। - केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के तहत आने वाले चबाने वाले तंबाकू वाली तैयारी। आबकारी अधिकारियों ने उत्तरदाताओं के कारखानों का निरीक्षण किया और पाया कि दिल्ली के कारखानों में निर्मित नशे की लत वाले मिश्रण (किमाम) को आर के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र लागू/प्राप्त किए बिना चबाने वाले तंबाकू के निर्माण के लिए गुप्त रूप से हटा दिया गया था। 174 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 और उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना। प्रतिवादियों को उत्पाद शुल्क और जुर्माना लगाने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। प्रत्यर्थियों ने अधिसूचना संख्या 121/94-सी ई दिनांक 11.08.1994 के तहत छूट का दावा किया और नियमों के अध्याय X में प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन का अनुरोध किया। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि छूट अधिसूचना का लाभ केवल तभी उपलब्ध होगा जब अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और प्रस्तुत किए गए अभिलेख प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन के अनुरोध की पुष्टि नहीं करते हैं। प्राधिकरण ने शुल्क देयता, ब्याज और जुर्माने के अधिरोपण को बरकरार रखा। पीड़ित, उत्तरदाताओं ने अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने अपीलों को यह कहते हुए अनुमति दी कि छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार नहीं किया जाना चाहिए यदि माल का इच्छित उपयोग स्थापित किया गया था, हालांकि नियमों के अध्याय X की प्रक्रियात्मक शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

निर्धारिती-2009 की सिविल अपील संख्या 568-569 में उत्तरदाता, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के तहत आने वाले पंप के पुर्जों और गन मेटल कास्टिंग/ढलाई के निर्माण में लगे हुए थे। आबकारी अधिकारियों ने निर्धारिती के कारखाने परिसर में तलाशी ली और पाया कि निर्धारिती ने छूट अधिसूचना संख्या की प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। 3/2001-सीई और 6/2001- सीई ने गुप्त रूप से उत्पाद शुल्क हटाने योग्य वस्तुओं को हटा दिया। एक नोटिस/सूचना जारी किया गया था। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने जुर्माने के साथ उत्पाद शुल्क की मांग की। आयुक्त (अपील) ने निर्धारिती द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अधिसूचना के लाभ को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था और अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन केवल प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा माल की प्राप्ति और उनके उपयोग को स्थापित करने के लिए किया जाना है।

निर्धारिती-अपीलार्थी, 2001 की सिविल अपील संख्या 1631 में, आबादी वाले मुद्रित सर्किट बोर्ड (पी. सी. बी.) के निर्माण में लगा हुआ था। उन्होंने पी. सी. बी. को अपनी इकाई से 'ओ' स्थान पर केंद्रीय स्टोर में स्थानांतरित कर दिया। अपील में, न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि निर्धारिती अधिसूचना संख्या 48/94- सीई दिनांक 1.3.1994 के लाभ के लिए पात्र नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के तहत आने वाले किसी निर्दिष्ट अंतिम उत्पाद का निर्माता अधिसूचनाओं के अनुसार निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने का पात्र है, यदि अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए इस आधार पर उपयोग किया

जाता है कि प्राप्तकर्ता की ओर से रखे गए रिकॉर्ड/अभिलेख केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के 'इच्छित उपयोग' और 'पर्याप्त अनुपालन' का संकेत देंगे।

2009 की सिविल अपील संख्या 1878-1880 और सिविल अपील संख्या 568-569 को अनुमति देना और 2001 की सिविल अपील संख्या 1631 को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

माना कि: 1.1 छूट या रियायत का दावा करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करना होगा कि वह उस छूट या रियायत का हकदार है। जैसा भी मामला हो, छूट, रियायत या अपवाद प्रदान करने वाले प्रावधान का कुछ अपवादों के साथ सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यह उस व्यवस्था पर निर्भर करता है जिस पर कानून में प्रावधान रखा गया है और उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। यदि कुछ शर्तों का पालन करने पर छूट उपलब्ध है, तो शर्तों का पालन करना होगा। उन शर्तों की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन या पूरा किया जाना चाहिए, हालांकि कभी-कभी, कुछ अक्षांश दिखाया जा सकता है, यदि कुछ आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता होती है जो प्रकृति में निर्देशिका हैं, जिसका पालन न करने से छूट देने वाली अधिसूचना का सार या सार प्रभावित नहीं होगा। [पैरा 22] [843-डी-एच; 844-ए]

नोवोपन इंडियन लिमिटेड, हैदराबाद बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टर, हैदराबाद (1994) पूरक 3 एससीसी 606; हंसराज गोरधनदास बनाम एच. एच. दवे (1996) 2 एस. सी. आर. 253-संदर्भित।

1.2 छूट अधिसूचना के कुछ प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका और कुछ अनिवार्य हो सकते हैं। कानून के प्रावधानों के बीच एक अंतर जो मूल चरित्र के हैं और बुरे थे! एक ओर नीति के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के साथ, और दूसरी ओर जो अपनी प्रकृति में केवल

प्रक्रियात्मक और तकनीकी हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से अलग रखा जाना चाहिए। इसलिए, एक पात्रता मानदंड एक सख्त निर्माण का हकदार है, हालांकि इसकी शर्त के निर्माण को एक उदार अर्थ दिया जा सकता है यदि वह प्रकृति में निर्देशिका है। [पैरा/कंडिका 23] [844-सी-ई]

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य (2005) 4 एस. सी. सी. 272-संदर्भित।

1.3 पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत प्रकृति में न्यायसंगत है, जिसे उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए बनाया गया है जहां एक पक्ष वह सब करता है जिसकी उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ छोटे या असंगत पहलुओं में विफल या त्रुटिपूर्ण है जिन्हें आवश्यकताओं के 'सार' या 'सार' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। 'तर्कसंगतता' की अवधारणा की तरह, 'पर्याप्त अनुपालन' की याचिका की स्वीकृति या अन्यथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य और पूर्व-आवश्यकताओं के संदर्भ पर निर्भर करता है जो नियम या विनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के बचाव का अनुरोध नहीं किया जा सकता है यदि एक स्पष्ट वैधानिक पूर्व-आवश्यकता जो कानून के उद्देश्य और उद्देश्य को प्रभावित करती है, को पूरा नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि अदालत को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि उस इरादे को पूरा किया जा सके जिसके लिए कानून को अधिनियमित किया गया था न कि सख्त अनुपालन की दर्पण छवि। पर्याप्त अनुपालन का अर्थ है "कानून के प्रत्येक उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक सी पदार्थ के संबंध में वास्तविक अनुपालन" और अदालत को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि कानून के इरादे को पूरा किया जा सके और उन उचित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जिनके लिए इसे पारित किया गया था। राजकोषीय कानून 0 आम तौर पर महत्वपूर्ण

नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है, विशेष रूप से जब कोई पक्ष छूट खंड का लाभ चाहता है। [पैरा/कंडिका 24] [844-एफ-जी; 845-ए-डी]

1.4 एक अधिनियम के पर्याप्त अनुपालन के सार पर जोर दिया जाता है, जहां अनिवार्य और निर्देशिका आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में, यदि अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो यह कहना उचित होगा कि निर्देशिका आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के बावजूद अधिनियम का काफी हद तक पालन किया गया है। ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त अनुपालन पाया गया है, कानून का वास्तविक अनुपालन हुआ है, हालांकि प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण है। [पैरा/कंडिका 24] [845-डी-एफ]

1.5 पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उन शर्तों या आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है जो कर या शुल्क छूट का आह्वान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और महत्वहीन और वास्तविक आवश्यकताओं या आवश्यकताओं के लिए गैर-अनुपालन को क्षमा करने का प्रयास करता है जो इतने भ्रमित या गलत तरीके से लिखे गए हैं कि अनुपालन के लिए एक गंभीर प्रयास को स्वीकार किया जाना चाहिए। पर्याप्त अनुपालन सिद्धांत की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए परीक्षण असंख्य मामलों का विषय रहा है और अक्सर, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आवश्यकताएं कानून के "सार" या "सार" से संबंधित हैं, यदि ऐसा है, तो उन आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना उस सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए एक पूर्व शर्त है। दूसरी ओर, यदि आवश्यकताएँ प्रक्रियात्मक या निर्देशिका हैं जिसमें वे किए जाने वाले कार्य के "सार" की नहीं हैं, लेकिन व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, तो उन्हें पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है, यदि सख्त अनुपालन नहीं है। केवल प्रयास किया गया अनुपालन

पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन कारकों का वास्तविक अनुपालन जो आवश्यक माने जाते हैं। [पैरा/कंडिका 24] [845-ई-एच; 846-ए-बी]

2.1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय X के प्रावधानों का अनुपालन निर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए एक पूर्व शर्त है, जो अन्यथा शुल्क आकर्षित करता है। सिविल अपील संख्या 1878-1880 में उत्तरदाताओं-मूल्यांकनकर्ताओं को कारण दर्शाएँ नोटिस /सूचना जारी किए गए थे, क्योंकि उन्होंने नियम 174 के साथ पठित धारा 6 के तहत पंजीकरण प्राप्त किए बिना और नियमों के नियम 9 (1), 52 ए, 53,54,1738,173 सी, 173 एफ और 226 के प्रावधानों का उल्लंघन करके (आपूर्तिकर्ता के छोर पर) उत्पाद शुल्क का निर्माण किया था, जिसके लिए शुल्क देयता, उस पर ब्याज और जुर्माना लगाया गया था। यह मानते हुए भी कि उत्तरदाता शुल्क से छूट के लिए पात्र थे, उत्तरदाताओं को आपूर्तिकर्ता की ओर से उत्पाद शुल्क के उत्पादन के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के कानूनी दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता था। [पैरा/कंडिका 18] [840-डी-एफ]

2.2 अधिसूचना संख्या 121/94-सी. ई. दिनांक 11.8.1994 का उद्देश्य और उद्देश्य उन निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं को छूट देना था, जो अन्यथा शुल्क के लिए कर योग्य थे, और मध्यवर्ती कर योग्य वस्तुओं के निर्माण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने से उत्तरदाताओं को छूट या छूट देना नहीं था। अध्याय X के तहत अधिसूचना को इस तरह से तैयार किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह एक अभिन्न अंग है। निर्दिष्ट अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच कृषि योग्य संबंध। अध्याय X के नियम 192 में कहा गया है कि छूट के तहत शुल्क मुक्त माल प्राप्त करने का इरादा रखने वाले निर्माता को विशेष औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क वस्तु प्राप्त करने के लिए

फॉर्म आर 1 में आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक वर्ग या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अनुमानित मात्रा और वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली ऐसी वस्तुओं के मूल्य, निर्मित की जाने वाली वस्तुओं और वर्ष के दौरान प्रत्येक वस्तु के अनुमानित उत्पादन और निकासी, निर्माण का तरीका, 0 उद्देश्य जिसके लिए निर्मित उत्पाद की आपूर्ति की जाती है और वह स्रोत जिससे उत्पाद शुल्क मुक्त माल प्राप्त किया जाएगा, का विवरण दिया जाता है। [पैरा/कंडिका 19] [841-जी-एच; 842-ए-सी]

2.3 नियम 192 के अनुसार प्रपत्र संख्या 1 में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और की जाने वाली घोषणा, अध्याय X के "सार" और "सार" से संबंधित है। आर-2 पंजीकरण प्रमाणपत्र भी सीटी-2 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यकता है। उस अध्याय में दिए गए बंधपत्रों का निष्पादन भी शुल्क मुक्त उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक खाली औपचारिकता नहीं है। बॉन्ड भी घोषणा के लिए जोर देते हैं। सीटी-2 प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब कोई पक्ष पंजीकरण प्राधिकरण से फॉर्म आर-2 के तहत पंजीकृत हो जाए। केवल अगर सीटी-2 प्रमाणपत्र हो। यदि प्राप्त किया जाता है, तो उत्पाद शुल्क को हटाया जा सकता है। प्रपत्र आर. जी. 16 रजिस्टर और प्रपत्र आर. टी. 11 में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण भी वैधानिक प्रकृति के हैं, जो अध्याय X के तहत आवश्यकताओं के "सार" और "सार" से संबंधित हैं। उन आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था। [पैरा/कंडिका 25] [846-बी-डी]

2.4 अपीलार्थियों की यह दलील कि उनके पास प्राप्तकर्ता के अंत में रखे गए रजिस्ट्रों में समान कॉलम थे और इसलिए, आपूर्तिकर्ता के अंत में अलग रजिस्टर बनाए रखने की आवश्यकता और छूट के लिए अध्याय X की आवश्यकताओं का काफी हद तक पालन किया गया था, कोई लाभ नहीं है। निर्धारित आरजी-16 रजिस्टर अध्याय X के लिए विशिष्ट था, जिसका एकमात्र उद्देश्य आपूर्तिकर्ता इकाई से प्राप्त शुल्क मुक्त प्रेषित आदानों

की प्राप्ति, जारी करने और उपयोग के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखना था। कॉलम की समानता और उसमें दिए गए विवरण को आरजी-16 रजिस्टर या अध्याय X के तहत शुल्क की छूट के लिए अन्य रजिस्ट्रों को बनाए नहीं रखने के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पैरा 26] [846-ई-जी]

2.5 आपूर्तिकर्ता की ओर से, नियम 174 के तहत कोई पंजीकरण प्राप्त नहीं किया गया था और कोई रिकॉर्ड/अभिलेख नहीं रखा गया था। आवेदक, प्राप्तकर्ता की ओर से, कानूनी रूप से वैधानिक प्रपत्रों में विभिन्न घोषणाएं देने के लिए भी बाध्य थे ताकि छूट का दावा किया जा सके और ऐसी घोषणाएं स्वीकार्य रूप से नहीं की गईं। उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय X में विभिन्न नियमों के तहत उल्लिखित उन शर्तों का पालन न करना और अध्याय X के तहत निर्धारित विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों को प्रस्तुत न करना, पर्याप्त अनुपालन और इच्छित उपयोग के अनुरोध के लिए घातक हैं। इसलिए, मामले के तथ्यों पर उत्तरदाता, अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के 'इच्छित उपयोग' या 'पर्याप्त अनुपालन' के अनुरोध को स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं ताकि दिनांकित 11.8.1994 छूट अधिसूचना के लाभ का दावा किया जा सके। [पैरा/कंडिका 27] [846-एच; 847-ए-सी]

थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम.सीमा शुल्क कलेक्टर (बॉम्बे) न्यू कस्टम हाउस (1992) 4 एस. सी. सी. 440; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, जयपुर बनाम जे. के. सिंथेटिक्स (2000) 10 एस. सी. सी. 393-विशिष्ट।

3. जहां तक 2009 की सिविल अपील संख्या 568-569 का संबंध है, न्यायाधिकरण के इस तर्क को बनाए रखना मुश्किल है कि अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया, केवल प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा माल की प्राप्ति और ए द्वारा उनके उपयोग को स्थापित करने के लिए है। न्यायाधिकरण ने अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आपूर्तिकर्ता की ओर से निर्मित वस्तुएं उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं थीं

और यदि कोई पक्ष शुल्क में छूट चाहता था; उसे कुछ पूर्व-अपेक्षाओं का पालन करना था, जिसका उद्देश्य यह देखना है कि छूट अधिसूचना की आड़ में माल को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट या उपयोग नहीं किया जाए। अध्याय X में विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं ताकि उन वस्तुओं के स्थानांतरण और दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके जो अन्यथा उत्पाद शुल्क योग्य हैं। इसलिए, "पर्याप्त अनुपालन" और "इच्छित उपयोग" की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा/कंडिका 34] [850-सी-ई]

4. जहाँ तक 2001 की सिविल/दीवानी अपील संख्या 1631 का संबंध है, न्यायाधिकरण ने पाया कि निर्धारिती अधिसूचना संख्या 48194-सी. ई. दिनांक 1.3.1994 के लाभ के लिए पात्र नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने पी. सी. बी. को अपनी इकाई से केंद्रीय दुकान में स्थानांतरित करके उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। 'ओ' न्यायाधिकरण ने अभিনিर्धारित किया कि अध्याय X के तहत, जो निर्धारिती छूट अधिसूचना का लाभ उठाना चाहता है, उसे अधिकार क्षेत्र वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को फॉर्म ए. एल.-6 में आवेदन दायर करना होता है और उसे ए. एल.-6 लाइसेंस प्राप्त करना होता है और उस अध्याय में निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना होता है जो शुल्क से छूट का दावा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। तथ्यों के साथ-साथ कानून पर भी न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा जाता है। (पैरा/कंडिका 31) [848-जी-एच; 849-ए-सी]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि चंद श्री गोपाल आदि। (2005) 8 एस. सी. सी. 164; नोवोपान इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टर, हैदराबाद (1994) सप 3 एस. सी. सी. 606; राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर, जयपुर, राजस्थान (1995) 4 एस. सी. सी. 473; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम एम.पी.वी इंजीनियरिंग

इंडस्ट्रीज (2003) 5 एस. सी. सी. 333; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स (2004) 11 एस. सी. सी. 801; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-1 बनाम महान डेयरी (2004) 11 एस. सी. सी. 798; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इलाहाबाद बनाम गिन्नी फिलामेंट्स लिमिटेड (2005) 3 एस. सी. सी. 378; सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम टुलो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड (2005) 13 एस. सी. सी. 789; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और अन्य। (2005) 4 एस. सी. सी. 272; साराभाई एम. केमिकल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, वडोदरा (2005) 2 एस. सी. सी. 168; झारखंड राज्य और सी. अन्य बनाम टाटा कमिंस लिमिटेड और ए. एन. आर. (2006) 4 एस. सी. सी. 57; ए. पी. स्टील री-रोलिंग मिल लिमिटेड आदि बनाम केरल राज्य और अन्य (2007) 2 एससीसी 725; उड़ीसा राज्य और ओआरएस. बनाम टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड (2007) 8 एस. सी. सी. 189; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर बनाम मेवाड़ बर्तान निर्मल उद्योग 2008 (239) ई. एल. टी. 27 (एस.सी.); हरियाणा राज्य जीपी सेरेमिक्स प्रा. लिमिटेड वी.आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश (2009) 2 एस. सी. सी. 90; गोपा जरदा उद्योग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2005) 8 एस. सी. सी. 157-संदर्भित।

वाद कानून संदर्भ:

(2005) 8 एस सी सी 164	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(1994) पूरक 3 एस सी सी 606	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(1995) 4 एस सी सी 473	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2003) 5 एस सी सी 333	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2004) 11 एस सी सी 801	संदर्भित किया गया	कंडिका 13

(2004) 11 एस सी सी 798	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2005) 3 एस सी सी 378	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2005) 13 एस सी सी 789	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2005) 4 एस सी सी 272	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2005) 2 एस सी सी 168	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2006) 4 एस सी सी 57	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2007) 2 एस सी सी 725	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2007) 8 एस सी सी 189	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
2008 (231) इ एल टी 27 (एस सी)	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
2008 (15) वी एस टी 176 (एस सी)	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2009) 2 एस सी सी 90	संदर्भित किया गया	कंडिका 13
(2008) 8 एस सी सी 157	संदर्भित किया गया	कंडिका 15
(1992) 4 एस सी सी 440	विशिष्ट	कंडिका 30
(2000) 10 एस सी सी 393	विशिष्ट	कंडिका 30

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 का दीवानी अपील सं.1878-1880

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली दिनांक 07.07.2023 के निर्णय और आदेश से अपील संख्या ई-2595/02-डी, ई/2596/02-डी और ई/2597/02-डी में।

साथ में

2001 का दीवानी अपील संख्या 1631 और 2009 का 568-569

विवेक तन्खा, ए. एस. जी., हरीश एन. साल्वे, रंजीत कुमार के स्वीमी, राहुल कौशिक, प्रतुल शांडिल्य, ऋषभ संचेती, सुमीर सोधी, वैभव श्रीवास्तव, डी. कुमानन, बी. के. प्रसाद श्रीकांत एन. तेरदल, आलोक यादव, वी. बालचंद्रन, एम. पी. देवनाथ, विवेक कोहली, अश्विनी शर्मा, सिद्धार्थ टंडन, मनोज गुप्ता, गायत्री गोस्वामी, राहुल चुघ, आशीष गर्ग, सुब्रमण्यम प्रसाद एस. गुरुकृष्णकुमार, श्रीकला गुरुकृष्ण कुमार, एस. आर. सेतिया उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय **के. एस. पनिकर राधाकृष्णन, न्यायमूर्ति** द्वारा दिया गया 1. इन अपीलों में जो प्रश्न विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "शुल्क अधिनियम") की अनुसूची के तहत आने वाले किसी निर्दिष्ट अंतिम उत्पाद का निर्माता अधिसूचना संख्या के अनुसार निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की छूट का लाभ प्राप्त करने का पात्र है, 121/94-सी.ई. दिनांक 11.8.1994, यदि अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए इस आधार पर आकर्षक रूप से उपभोग किया जाता है कि प्राप्तकर्ता के अंत में उसके द्वारा रखे गए अभिलेख केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में 'उत्पाद शुल्क नियम') के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के "इच्छित उपयोग" और "पर्याप्त अनुपालन" का संकेत देंगे।

2. उपरोक्त प्रश्न का निर्णय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा उत्तरदाता-निर्धारकों के पक्ष में किया गया था थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (बॉम्बे) नया कस्टम हाउस (1992) 4 एस. सी. सी. 440 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर बनाम जे. के. सिंथेटिक्स (2000) 10 एस. सी. सी. 393 "इच्छित उपयोग" और "पर्याप्त अनुपालन" के सिद्धांत के

आधार पर इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया। यह मामला इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आया जिसने उपरोक्त निर्णयों की शुद्धता और प्रयोज्यता पर संदेह किया और यह विचार रखा कि छूट अधिसूचना में जहां तक पात्रता का संबंध है, सख्त व्याख्या की आवश्यकता है, विशेष रूप से जब कोई निर्धारिती केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 5ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत शुल्क से छूट चाहता है, जिसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की धारा 3ए की उप-धारा (3) के साथ पढ़ा जाता है उत्पाद शुल्क के अतिरिक्त शुल्क (निर्दिष्ट महत्व के सामान) अधिनियम 1957 की धारा 3, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और जे. के. सिंथेटिक्स (ऊपर) में, इस न्यायालय को ऐसी स्थिति से निपटा गया था जहां देश के बाहर से माल का आयात किया गया था, वर्तमान मामले के विपरीत जहां निर्दिष्ट मध्यवर्ती सामान उत्तरदाताओं की कुछ अन्य इकाईयों में स्थानीय रूप से निर्मित थे। अदालत ने आदेश दिया कि मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया गया है। संदर्भ का आदेश आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली बनाम हरि चंद श्री गोपाल आदि। (2005) 8 एससीसी 164 में सूचित किया गया है।

3. हम सबसे पहले 2004 की सिविल अपील संख्या 1878-1880 में तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं, जिसे प्रमुख मामले के रूप में लिया जाता है।

तथ्य:

4. इसमें उत्तरदाता मैसर्स गोपाल इंडस्ट्रीज, मैसर्स हरि चंद श्री गोपाल और मैसर्स गोपाल जरदा उद्योग उत्पाद शुल्क हटाने योग्य वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए थे। अध्याय

शीर्षक सं. 2404.40 के अंतर्गत आने वाला तंबाकू। टैरिफ अधिनियम का तब शुल्क की शून्य दर के लिए प्रभावी था, जिसे 1.3.1994 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए प्रभावी बनाया गया था। विभाग की खुफिया शाखा को पता चला कि प्रतिवादी उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 174 के तहत आवश्यक पंजीकरण प्रमाण पत्र को लागू किए बिना/प्राप्त किए बिना उक्त वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना और किसी भी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें अपने कारखानों से गुप्त रूप से हटा रहे थे। यह देखा गया कि उपरोक्त निर्मित वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा मैसर्स गोपाल जरदा उद्योग (मेरठ), मैसर्स हरि चंद श्री गोपाल, बददी जिला, सोलन (एच. पी.) और मैसर्स गोपाल इंडस्ट्रीज, बददी (एच. पी.) को 'हस्तांतरण चालान' की आड़ में भेजा गया था, जिसमें उक्त वस्तुओं को 'अतिरिक्त उत्पाद' या 'किमाम/के' के रूप में वर्णित किया गया था। 28.9.1996 को, दिल्ली में उत्तरदाताओं के कारखानों का निरीक्षण एमओडी IV, दिल्ली के केंद्रीय उत्पाद शुल्क (निवारक) अधिकारी द्वारा किया गया और तैयार उत्पादों के नमूने लिए गए और फर्मों के भागीदारों से विस्तृत बयान भी दर्ज किए गए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने 3.10.1996 को सोलन और बददी में उत्तरदाताओं के विभिन्न कारखानों का भी दौरा किया और यह देखा गया कि नशे की लत दिल्ली के कारखानों में निर्मित मिश्रण (किमाम) को चबाने वाले तंबाकू के निर्माण के लिए गुप्त रूप से हटाया जा रहा था। अधिकारियों ने देखा कि उत्तरदाता अध्याय उप-शीर्षक संख्या के तहत टैरिफ अधिनियम के तहत आने वाले उत्पाद शुल्क का उत्पादन कर रहे थे। 2404.49 (22.7.1996 तक) और, 23.7.1996 से प्रभावी, अध्याय उपशीर्षक संख्या- 2404.40, के अंतर्गत आता है। 2404.40 ने इसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना खरीदार/उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के कंटेनरों में पैक किया, जो कि 14.10.1996 तक उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 174 के साथ पढ़ा जाता है और इसे उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9

(1), 52 ए, 53,54,173 बी, 173 सी, 173 एफ और 226 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना गुप्त रूप से अपने कारखानों से हटा दिया।

5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने देखा कि 18.3.1994 से 15.4.1995 की अवधि के दौरान, मेसर्स गोपाल जरदा उद्योग ने अपने कारखाने से कुल 1,52,226.150 किलोग्राम कीमाम युक्त तैयारी का निर्माण और हटाया था। इसका मूल्य 15,27,90,675.00 रु. था और इसमें शामिल शुल्क की राशि 6,14,17,770.00 रु. तय की गई थी।

6. मेसर्स गोपाल इंडस्ट्रीज ने 16.06.1995 से 26.09.1996 तक की अवधि के दौरान, अपने कारखाने से कुल 2,66,648.800 कि. ग्रा. की किमाम युक्त तैयारी का निर्माण और निष्कासन किया था, जिसका सामूहिक मूल्य 16,26,68,569.00 था और इसमें शामिल शुल्क की राशि 8,13,34,285.00 निर्धारित की गई थी।

7. मेसर्स हरि चंद श्री गोपाल ने भी, 14.6.1995 से 24.9.1996 की अवधि के दौरान अपने कारखाने से कुल 1,51,054.900 किलोग्राम की किमाम युक्त तैयारी का निर्माण और निष्कासन किया था, जिसका सामूहिक मूल्य Rs.15,86,77,319.00 था और इसमें शामिल शुल्क की राशि 7,93,38.660.00 निर्धारित की गई थी।

8. नतीजतन, 25.03.1997 को, प्रत्यर्थियों और उनके भागीदारों को कारण दिखाने के लिए नोटिस जारी किए गए कि शुल्क अधिनियम की धारा 11 ए (1) के प्रावधान के साथ पठित उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 (2) के तहत उनसे संयुक्त रूप से और अलग-अलग शुल्क की राशि की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए और शुल्क अधिनियम की धारा 11 एबी के तहत उन पर ब्याज की मांग क्यों नहीं की जानी चाहिए। दंड शुल्क अधिनियम की धारा 11 एसी के साथ पठित उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 173 क्यू और उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 209 ए के तहत भी मांग की गई थी। उपरोक्त के अलावा, उत्तरदाताओं से यह भी कारण बताने के लिए कहा गया था कि किमाम के निर्माण के लिए उनके संबंधित कारखानों

में उपयोग की जाने वाली भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी को आबकारी नियमों के नियम 173 क्यू (2) के तहत जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

9. उत्तरदाताओं ने कारण दर्शाओ नोटिस पर विस्तृत आपत्तियां दायर कीं और अपने दायित्व पर विवाद किया और अधिसूचना संख्या- 121/94-CE के तहत छूट का भी दावा किया। आयुक्त (उत्पाद शुल्क) ने अपने दिनांक 20.5.1998 के आदेश द्वारा कारण बताए जाने के नोटिसों के खिलाफ प्रतिवादियों द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया और निर्धारित किया कि मैसर्स गोपाल जरदा उद्योग, मैसर्स गोपाल इंडस्ट्रीज और मैसर्स हरि चंद श्री गोपाल केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, क्रमशः 6,14,17,770/- रु., 8,13,34,285/- रु. और 7,93,38,660/- रु. तथा उन पर उत्पाद शुल्क अदा करें और 16,00,000/- रु. का जुर्माना भी लगाया उन पर उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 173 क्यू. के तहत 18,00,000/- रु. और 17,00,000/- रु. का जुर्माना लगाया और मैसर्स गोपाल इंडस्ट्रीज और मैसर्स हरिचंद श्री गोपाल के परिसर से जब्त किए गए माल के जब्त करने का आदेश दिया, माल छुड़ाने की अनुमति 5,00,000/- रु. और रु. 3,20,000- क्रमशः के जुर्माने के मोचन पर।

10. उपर्युक्त आदेशों से व्यथित होकर, न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलें दायर की गईं और न्यायाधिकरण दिनांक 01.10.1999 के आदेश के माध्यम से, जो प्रश्नगत वस्तुओं पर शुल्क देयता पर न्यायनिर्णायक आयुक्त के निष्कर्षों के साथ-साथ सीमा के मुद्दे के साथ-साथ प्रोफार्मा क्रेडिट/मोडवेट क्रेडिट के दावे पर भी सहमत थीं, लेकिन अधिसूचना दिनांक 11.08.1994 की सं.- 121/94 सीई की प्रयोज्यता के सीमित प्रश्न की फिर से जांच का आदेश दिया क्योंकि उत्तरदाताओं ने यह तर्क दिया था कि उन्होंने अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रियाओं का काफी हद तक पालन किया था। प्रत्यर्थियों ने आयुक्त के समक्ष तर्क दिया कि उन्होंने चालान स्थानांतरित करने के बावजूद माल को अपनी अंतिम विनिर्माण इकाइयों में

भेज दिया था और प्राप्तियों को फॉर्म-IV रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया था और माल का उपयोग आरजी-12 रजिस्टर में दर्ज किया गया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि उत्तरदाताओं द्वारा निर्मित अंतिम उत्पादों का पता आरजी-1 रजिस्टर से लगाया जा सकता है। प्राप्तकर्ता और वे अभिलेख माल के उपयोग को स्थापित करने और शुल्क छूट के लिए अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन के अनुरोध को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे।

11. आयुक्त ने अपने दिनांक 16.07.2002 के आदेश के माध्यम से सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि छूट अधिसूचना का लाभ केवल तभी उपलब्ध होगा जब अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेख उपरोक्त अध्याय में निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन के अनुरोध की पुष्टि नहीं करेंगे। इसलिए शुल्क देयता, ब्याज और जुर्माना लगाने की पुष्टि की गई।

12. प्रतिवादियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में मामले को उठाया। न्यायाधिकरण, हमने पहले ही संकेत दिया है, थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और जे. के. सिंथेटिक्स (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखता है और यह विचार रखता है कि छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार नहीं किया जाना चाहिए यदि माल का "इच्छित उपयोग" स्थापित किया गया था, हालांकि अध्याय X की प्रक्रियात्मक शर्तों का पालन नहीं किया गया था। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई थी और आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर दिया गया था। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश से व्यथित, इन अपीलों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा प्राथमिकता दी गई है।

13. राजस्व की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त महान्यायभिकर्ता श्री विवेक तन्खा ने कहा कि अधिसूचना सं. 121/94-सी.ई. दिनांकित 11.8.94 उत्तरदाताओं के लिए केवल तभी उपलब्ध होगा जब अध्याय X के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन

किया जाए। विद्वान अ. म. न्या. ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण द्वारा शुल्क देयता की पुष्टि की गई थी जो इंगित करेगी कि आपूर्तिकर्ताओं की ओर से उत्तरदाताओं ने आबकारी नियमों के नियम 9 (1), 52 ए, 53, 54, 173 बी, 173 सी, 173 एफ और 226 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था और इसी कारण से, उत्तरदाताओं को 25.03.1997 दिनांकित कारण दिखाएँ नोटिस जारी किए गए थे। विद्वान अ. म. न्या. ने प्रस्तुत किया कि केवल यह तथ्य कि उत्तरदाताओं ने प्राप्तकर्ता की ओर से कुछ अभिलेख बनाए रखे थे, उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के "इच्छित उपयोग" या "पर्याप्त अनुपालन" के अनुरोध को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि छूट अधिसूचना का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और निर्धारिती को खुद को अधिसूचना के दायरे में लाना चाहिए। निर्णयों का संदर्भ इस न्यायालय ने नोवोपन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त, हैदराबाद (1994) पू.3 एस. सी. सी. 606, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर, राजस्थान (1995) 4 एस. सी. सी. 473, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम एम. पी. वी. और इंजीनियरिंग उद्योग (2003) 5 एस. सी. सी. 333, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, त्रिची बनाम रुक्मिणी पाकवेल ट्रेडर्स (2004) 11 एस. सी. सी. 801, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़-1 बनाम महान डेयरी (2004) 11 एस. सी. सी. 798, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इलाहाबाद बनाम गिन्नी फिलामेंट्स लिमिटेड (2005) 3 एस. सी. सी. 378, सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम टुलो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड (2005) 13 एस. सी. सी. 789, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम। झारखंड राज्य और अन्य। (2005) 4 एस. सी. सी. 272, साराभाई एम. केमिकल्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, वडोदरा (2005) 2 एस. सी. सी. 168, झारखंड राज्य और अन्य बनाम टाटा कमिंस लिमिटेड और एक अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. 57, ए. पी. स्टील री-रोलिंग मिल लिमिटेड आदि बनाम केरल राज्य और अन्य। (2007) 2 एस. सी. सी. 725,

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड (2007) 8 एस. सी. सी. 189, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर बनाम मेवाड़ बर्तन निर्मल उद्योग 2008 11 (231) ईएलटी 27 (एससी), हरियाणा राज्य बनाम समटेल इंडिया लिमिटेड 2008 (15) वी. एस. टी. 176 (एस. सी.) और जी. पी. सिरेमिक प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश (2009) 2 एससीसी 90।

14. दूसरी ओर, निर्धारिती-प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि निर्धारिती ने यह साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि किमाम की पूरी मात्रा उनकी एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित की गई थी और इसका उपयोग ब्रांडेड चबाने वाले तंबाकू के निर्माण में किया गया था और शुल्क का भुगतान करने पर इसे हटा दिया गया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि निर्धारिती ने स्थानांतरण चालान प्रस्तुत किए थे जिसके तहत किमाम को दूसरी इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने किमाम की प्राप्ति के संबंध में फॉर्म IV रजिस्टर/स्टॉक रजिस्टर और उत्पाद शुल्क वाले तंबाकू उत्पादों के निर्माण के लिए रखे गए फॉर्म आरजी-12 का भी संदर्भ दिया। नियम 47,53 और 173 जी के तहत बनाए गए आरजी-1 रजिस्टर का संदर्भ दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उन अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए किमाम के इच्छित उपयोग (वास्तविक उपयोग) को स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और जे. के. सिंथेटिक्स (ऊपर), के निर्णयों के अनुसार छूट अधिसूचना के लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता है यदि अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन किया गया है और अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए माल का इच्छित उपयोग स्थापित किया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अध्याय X में निर्धारित शर्तें केवल प्रक्रियात्मक प्रकृति की हैं और इसलिए निर्देशिका, उदार निर्माण की गारंटी देती है, और यदि ऐसा माना जाता है, तो छूट अधिसूचना के लाभ से

इनकार नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण और कुछ उच्च न्यायालय उपरोक्त सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) और जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड (उपर) में निर्धारित सिद्धांतों को समान रूप से लागू कर रहे हैं।

15. हम, संबंधित पक्षों द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों की जांच करने से पहले, यह इंगित कर सकते हैं कि प्रत्यर्थियों ने पहले 2000 की सी. ए. संख्या 5747-5749 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि किमाम उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 11 (ए) (1) के प्रावधान के तहत परिसीमन की विस्तारित अवधि को लागू करने में विभाग सही था। इस न्यायालय ने आंशिक रूप से इन अपीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि विभाग आबकारी अधिनियम की धारा 11 (ए) (1) के प्रावधान के तहत परिसीमन की विस्तारित अवधि को लागू करने का हकदार नहीं था, लेकिन यह माना कि नशे की लत का मिश्रण किमाम उप-शीर्षक 2404.49 2404.40 के तहत हटाने योग्य और वर्गीकृत करने योग्य था। इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि हालांकि नियम 174 के साथ पठित धारा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था और उन्होंने दिल्ली में इकाइयों में उत्पाद शुल्क के उत्पादन के लिए नियमों का पालन नहीं किया था, लेकिन शुल्क के भुगतान से बचने का कोई इरादा नहीं था। गोपाल जरदा उद्योग बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (2005) 8 एस. सी. सी. 157 में निर्णय की सूचना दी गई है।

16. इस मामले में, हम केवल इस सवाल से चिंतित हैं कि क्या प्रतिवादी उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के "इच्छित उपयोग" और "पर्याप्त अनुपालन" के आधार पर दिनांकित 11.8.1994 छूट अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

17. अधिसूचना सं। 121/94-सी.ई. दिनांक 11.8.1994 केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 (1994 का 1) की धारा 5ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था, जिसे अतिरिक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पढ़ा जाता है। उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) कुछ निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं को छूट देने के लिए जनहित में, यदि उन वस्तुओं का विशिष्ट अंतिम उत्पादों के निर्माण में आकर्षक रूप से उपभोग किया गया था, जो टैरिफ अधिनियम की अनुसूची की शीर्ष संख्या या उप-शीर्षक संख्या के तहत आते हैं। अधिसूचना में यह भी निर्धारित किया गया है कि जहां निवेश का ऐसा उपयोग किसी निर्माता के कारखाने में होता है, जो उसके कारखाने से अलग होता है, जहां माल का उत्पादन किया गया था, इस अधिसूचना में निहित छूट आबकारी नियमों के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया के पालन के अधीन मान्य होगी। हम जिस तालिका से संबंधित हैं, वह नीचे दी गई है:

क्रम सं.	अंतिम उत्पादों का विवरण	अंतिम उत्पादों की शीर्षक संख्या या उप-शीर्षक संख्या	शीर्षक संख्या या उप-शीर्षक इनपुट की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx
2.	चबाने वाला तंबाकू जिसमें आम तौर पर "खड़ा मसाला", "किमाम", "डोकता", "जरदा", "सुखा" और	2401.41	2404.49

xxx	"सुरती" के रूप में जाना जाने वाला व्यंजन शामिल हैं। xxx xxx xxx	xxx xxx xxx	xxx xxx xxx
-----	---	--------------------------	--------------------------

18. अध्याय 10 के प्रावधानों का अनुपालन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने के लिए एक पूर्व शर्त है, जो अन्यथा शुल्क को आकर्षित करता है। उत्तरदाताओं को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किए गए थे क्योंकि उन्होंने नियम 9 (1), 52 ए, 53, 54, 173 बी, 173 सी, 173 एफ और 226 के प्रावधानों का उल्लंघन करके नियम 174 के साथ पठित धारा 6 के तहत पंजीकरण प्राप्त किए बिना (आपूर्तिकर्ता की ओर) उत्पाद शुल्क योग्य मामला निर्माण किया था, जिसके लिए शुल्क देयता, उस पर ब्याज और जुर्माना लगाया गया था। यह मानते हुए भी कि उत्तरदाता शुल्क से छूट के लिए पात्र थे, उत्तरदाताओं को आपूर्तिकर्ता की ओर से उत्पाद शुल्क के उत्पादन के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के कानूनी दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता था।

19. दिनांक 11.8.1994 की अधिसूचना का प्रयोजन और लक्ष्य उन निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं को छूट देना था, जो अन्यथा शुल्क के योग्य थे, और मध्यवर्ती उत्पाद शुल्क के लिए वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने से उत्तरदाताओं को छूट या छूट देना नहीं था। अध्याय X के तहत अधिसूचना को इस तरह से तैयार किया गया था ताकि यह निर्दिष्ट अंतिम उत्पादों के निर्माण के लिए उत्पाद शुल्क के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच अविभाज्य संबंध सुनिश्चित किया जा सके। अध्याय 10 के नियम 192 में कहा गया है कि छूट के तहत शुल्क मुक्त माल प्राप्त करने के इच्छुक निर्माता को विशेष औद्योगिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद शुल्क वस्तु प्राप्त करने के लिए फॉर्म आर-1 में

आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक वर्ग या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की अनुमानित मात्रा और वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली ऐसी वस्तुओं के मूल्य, निर्मित की जाने वाली वस्तुओं और वर्ष के दौरान प्रत्येक वस्तु के अनुमानित उत्पादन और निकासी, निर्माण का तरीका, जिस उद्देश्य के लिए निर्मित उत्पाद की आपूर्ति की जाती है और वह स्रोत जिससे उत्पाद शुल्क मुक्त माल प्राप्त किया जाएगा, का विवरण दिया जाता है।

20. प्रपत्र आर-1 में दिए गए विवरण के आधार पर, पंजीकरण प्राधिकरण को शुल्क में छूट से अनुमति देने पर विचार करना होगा। उक्त उद्देश्य के लिए, आर-2 प्रमाणपत्र यह निर्दिष्ट करते हुए जारी किया जाना आवश्यक है कि पंजीकरण प्रमाण पत्र नियम 192 के तहत उत्पाद शुल्क योग्य माल प्राप्त करने के लिए है। आर-2 प्रमाणपत्र के आधार पर, निर्माता उस उत्पाद को प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाता है जिसके लिए शुल्क में छूट मांगी गई है। इसके अलावा, आवेदक को प्रपत्र में प्रतिभूति के साथ एक बांड निष्पादित करने की भी आवश्यकता होती है बी-8, जैसा कि नियम 192 के तहत आवश्यक है और आयुक्त शुल्क की छूट के लिए दी गई अनुमति के दौरान बी-16 बॉन्ड या बी-17 बॉन्ड दाखिल करने के लिए और शर्तें रख सकते हैं। इस तरह के अनुरोध पर और सभी वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद, क्षेत्राधिकार अधिकारी को सी-2 प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है और उस प्रमाण पत्र के बल पर, आवेदक शुल्क मुक्त सामान प्राप्त कर सकता है। क्षेत्राधिकार अधिकारी को यह भी प्रमाणित करना होगा कि उक्त निर्माता नियम 192 के तहत अपनी सीमा में पंजीकृत है और अपने कारखाने में निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क योग्य माल के निर्माण के लिए विशेष औद्योगिक उद्देश्य में उपयोग के लिए शुल्क की रियायती दर पर उत्पाद शुल्क प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। इसके अलावा, सी-2 प्रमाण पत्र के बल पर, उत्पाद शुल्क या शुल्क की रियायती दर के भुगतान जैसा मामला हो, के बिना स्रोत निर्माता के कारखाने से उत्पाद शुल्क को हटाया जा सकता है। इसके अलावा, नियम 194 के उप-नियम (1) के अनुसार, आवेदक को फॉर्म आर.जी. 16 रजिस्टर में मात्रा,

मूल्य, दर और शुल्क की राशि, अंक और संख्या/अपव्यय आदि का संकेत देते हुए ऐसी वस्तुओं का उचित अभिलेख रखना आवश्यक है। इसके अलावा, आवेदक को आर. टी. 11 के रूप में त्रैमासिक विवरणी भी दाखिल करनी होती है और उस विवरणी में, पंजीकृत व्यक्ति को माल की प्राप्ति, उसके लिए जारी की गई मात्रा के विवरण के बारे में प्रविष्टियां करनी होती हैं। विनिर्माण, अपव्यय या अन्य नुकसान, उस प्रक्रिया का विवरण जिसमें उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु का उपयोग किया जाना है आदि। माल के आपूर्तिकर्ता को नियम 174 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है और आरटी-12 के कॉलम 10 (i) या 10 (ii) में अध्याय X के तहत सुविधा का लाभ उठाने वाले निर्धारिती को भेजे गए माल का विवरण भी उल्लेख करना आवश्यक है। माल का आपूर्तिकर्ता केवल उचित गेट पास जीपी-1 के तहत माल को हटा सकता है और गेट पास पर सीटी-2 के विवरण का उल्लेख करना आवश्यक है।

21. नियम 196 प्राप्तकर्ता द्वारा शुल्क के भुगतान का प्रावधान करता है यदि नियम 192 के तहत प्राप्त माल का लेखा-जोखा नहीं है या इन नियमों के तहत निर्धारित तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह, नियम 196 ए में कहा गया है कि नियम 192 के तहत प्राप्त अधिशेष माल को शुल्क के भुगतान पर मंजूरी दी जा सकती है। नियम 196 ए. नियम 192 के तहत प्राप्त ऐसी वस्तुओं को किसी अन्य निर्माता को हस्तांतरित करने का प्रावधान करता है जिसे उचित अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ नियम 192 के तहत पंजीकरण दिया गया है। नियम 196 बी उस तरीके का प्रावधान करता है जिसमें नियम 192 के तहत प्राप्त माल का निपटान किया जा सकता है यदि वह दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त पाया जाता है, तो उन्हें मूल निर्माता को वापस किया जा सकता है और ऐसे लौटाए गए माल को मूल निर्माता के साथ जोड़ा जाएगा मूल निर्माता और ऐसे लौटाए गए सामान को मूल निर्माता के गैर-शुल्क भुगतान स्टॉक में जोड़ा जाएगा। अंत में, नियम 196 बीबी नियम 192 के तहत प्राप्त माल की आवाजाही के लिए या मरम्मत और वापसी के लिए कारखाने के

बाहर आंशिक प्रसंस्करण के बाद प्रदान करता है। आवेदक, हालांकि नियम 174 के तहत पंजीकृत है, विशेष औद्योगिक उद्देश्य में उपयोग के लिए प्रेषित माल केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब उसे पंजीकरण प्रमाणपत्र पर उस प्रभाव का समर्थन मिलता है, जो पहले से फॉर्म आर-2 में दिया गया था, जो इस मामले में घटना के बाद केवल 22.10.1996 पर प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, आर-1 प्रमाणपत्र की अनुसूची का कॉलम 5 स्पष्ट रूप से प्राप्तकर्ता इकाई को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने का आदेश देता है जैसे कि औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं का विवरण, वर्ष में अनुमानित मात्रा, माल के आपूर्तिकर्ता का विवरण आदि। इसके अलावा, आर-2 प्रमाण पत्र के आधार पर, क्षेत्राधिकार रेंज अधिकारी एक सीटी-2 प्रमाण पत्र (माल के हस्तांतरण के लिए प्रमाण पत्र) जारी करता है, जिसके कवर के तहत प्रेषित माल को आपूर्तिकर्ता इकाई से प्राप्तकर्ता इकाई में ले जाना होता है। सीटी-2 प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ता इकाई को दिखाया जाना आवश्यक है जो सीटी-2 प्रमाण पत्र के बल पर शुल्क का भुगतान किए बिना माल वितरित करने से पहले गेट पास पर सीटी-2 संख्या का उल्लेख करेगा। उपर्युक्त का अनुपालन अध्याय 10 में निर्धारित आवश्यकताएं, निर्दिष्ट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की छूट से छूट प्राप्त करने के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है।

छूट खंड-सख्त निर्माण

22. कानून अच्छी तरह से तय है कि छूट या रियायत का दावा करने वाले व्यक्ति को यह स्थापित करना होगा कि वह उस छूट या रियायत का हकदार है। यथास्थिति, छूट, रियायत या अपवाद प्रदान करने वाले प्रावधान का कुछ अपवादों के साथ सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, जो उस व्यवस्था पर निर्भर करता है जिस पर प्रावधान को कानून में रखा गया है और लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है। यदि कुछ शर्तों का पालन करने पर छूट उपलब्ध है, तो शर्तों का पालन करना होगा। उन शर्तों की अनिवार्य

आवश्यकताओं का पालन या पूरा किया जाना चाहिए, हालांकि कभी-कभी, कुछ विस्तार दिखाया जा सकता है, यदि कुछ आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता होती है जो प्रकृति में निर्देशिका हैं, जिसका पालन न करने से छूट देने वाली अधिसूचना का सारांश या सार प्रभावित नहीं होगा। नोवोपैन इंडियन लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक व्यक्ति को, उसे कर देयता से मुक्त करने के लिए, एक अपवाद या छूट प्रावधानों का आह्वान करते हुए, स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि वह उक्त प्रावधान के दायरे में आता है, उक्त प्रावधान के अधीन और, संदेह या अस्पष्टता के मामले में, इसका लाभ राज्य को जाना चाहिए। हंसराज गोरधनदास बनाम एच. एच. दवे (1996) 2 एस. सी. आर. 253 में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि इस तरह की अधिसूचना की व्याख्या उसके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के आलोक में की जानी चाहिए न कि किसी अन्य आधार पर। यह इस सिद्धांत के संदर्भ में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया था कि एक कर कानून में, किसी भी इरादे के लिए कोई जगह नहीं है, उस संबंध में शब्दों के स्पष्ट अर्थ को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह कि मामला पूरी तरह से अधिसूचना की भाषा, यानी छूट की स्पष्ट शर्तों द्वारा शासित होना चाहिए।

23. बेशक, छूट अधिसूचना के कुछ प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका हो सकते हैं और कुछ प्रकृति में अनिवार्य हैं। कानून के उन प्रावधानों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए जो मूल प्रकृति के हैं और जो एक ओर नीति के कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के साथ बनाए गए थे, और दूसरी ओर जो अपनी प्रकृति में केवल प्रक्रियात्मक और तकनीकी हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में, यह न्यायालय अभिनिर्धारित किया कि छूट अधिसूचना के निर्माण के संबंध में सिद्धांत अब एकीकृत नहीं हैं; जबकि पात्रता खंड छूट अधिसूचना के संबंध में सख्त अर्थ दिया जाता है, जिसके लिए अधिसूचना की व्याख्या उसकी भाषा के संदर्भ में की जानी चाहिए, एक बार जब कोई निर्धारिती पात्रता खंड को संतुष्ट कर देता है, तो उसमें छूट खंड का शाब्दिक अर्थ लगाया जा सकता है। एक पात्रता

मानदंड, इसलिए, एक सख्त निर्माण का हकदार है, हालांकि इसकी शर्त के निर्माण को एक उदार अर्थ दिया जा सकता है यदि वह प्रकृति में निर्देशिका है।

पर्याप्त अनुपालन और इच्छित उपयोग का सिद्धांत:

24. पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत एक न्यायिक आविष्कार है, जो प्रकृति में न्यायसंगत है, जिसे उन मामलों में कठिनाई से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है जहां एक पक्ष वह सब करता है जो उचित रूप से उससे उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कुछ छोटे या असंगत पहलुओं में विफल या त्रुटिपूर्ण है जिन्हें आवश्यकताओं के "सारांश" या "सार" के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। "तर्कसंगतता" की अवधारणा की तरह, "पर्याप्त अनुपालन" की याचिका की स्वीकृति या अन्यथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन और उद्देश्य और पूर्व शर्तों के संदर्भ पर निर्भर करता है जो नियम या विनियमन के प्रयोजन और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के एक बचाव का अनुरोध नहीं किया जा सकता है यदि एक स्पष्ट वैधानिक पूर्व शर्त जो कानून के लक्ष्य और उद्देश्य को प्रभावित करती है, को पूरा नहीं किया गया है। निश्चित रूप से, इसका अर्थ है कि न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि उस इरादे को पूरा किया जा सके जिसके लिए कानून को अधिनियमित किया गया था, न कि सख्त अनुपालन की दर्पण छवि। पर्याप्त अनुपालन का अर्थ है "कानून के प्रत्येक उचित उद्देश्य के लिए आवश्यक पदार्थ के संबंध में वास्तविक अनुपालन" और अदालत को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या कानून का पर्याप्त रूप से पालन किया गया है ताकि कानून के इरादे को पूरा किया जा सके और उन उचित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके जिनके लिए इसे पारित किया गया था। राजकोषीय कानून आम तौर पर महत्वपूर्ण नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है, विशेष रूप से जब कोई पक्ष एक

छूट खंड का लाभ चाहता है जो महत्वपूर्ण है। एक अधिनियम के पर्याप्त अनुपालन पर जोर दिया जाता है, जहां अनिवार्य और निर्देशिका आवश्यकताओं को एक साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में, यदि अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किया जाता है, तो यह कहना उचित होगा कि निर्देशिका आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के बावजूद अधिनियम का काफी हद तक पालन किया गया है। ऐसे मामलों में जहां पर्याप्त अनुपालन पाया गया है, वहां वास्तविक अनुपालन किया गया है कानून, यद्यपि प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण है। पर्याप्त अनुपालन का सिद्धांत उन शर्तों या आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को बनाए रखने का प्रयास करता है जो कर या शुल्क छूट का आह्वान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और या तो महत्वहीन और वास्तविक आवश्यकताओं या आवश्यकताओं के लिए गैर-अनुपालन को क्षमा करने का प्रयास करता है जो इतने भ्रमित या गलत तरीके से लिखे गए हैं कि अनुपालन में एक गंभीर प्रयास को स्वीकार किया जाना चाहिए। पर्याप्त अनुपालन सिद्धांत की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए परीक्षण असंख्य मामलों का विषय रहा है और अक्सर, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या आवश्यकताएं कानून के "सार" या "सारांश" से संबंधित हैं, यदि ऐसा है, तो उन आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करना उस सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए एक पूर्व शर्त है। दूसरी ओर, यदि आवश्यकताएँ प्रक्रियात्मक या निर्देशिका हैं जिसमें वे किए जाने वाले कार्य के "सार" की नहीं हैं, लेकिन व्यवसाय के व्यवस्थित संचालन को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, तो उन्हें पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है, यदि सख्त अनुपालन नहीं है। दूसरे शब्दों में, केवल अनुपालन का प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन उन कारकों का वास्तविक अनुपालन जो आवश्यक माने जाते हैं।

25. नियम 192 के अनुसार प्रपत्र संख्या 1 में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और की जाने वाली घोषणा, अध्याय X के "सार" और "सारांश" से संबंधित है। आर-2 पंजीकरण प्रमाणपत्र भी सीटी-2 प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पूर्व-आवश्यकता है। इसके अलावा, उस अध्याय में दिए गए बॉन्ड का निष्पादन भी शुल्क मुक्त उत्पाद शुल्क प्राप्त करने के लिए एक खाली औपचारिकता नहीं है। बॉन्ड भी घोषणा के लिए जोर देते हैं। सीटी-2 प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब कोई पक्ष पंजीकरण प्राधिकरण से फॉर्म आर-2 के तहत पंजीकृत हो जाए। यदि सीटी-2 प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो ही उत्पाद शुल्क हटाने योग्य सामान को हटाया जा सकता है। प्रपत्र आर. जी. 16 रजिस्टर और प्रपत्र आर. टी. 11 में प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण भी वैधानिक प्रकृति के हैं, जो अध्याय 10 के तहत आवश्यकताओं के "सार" और "सारांश" से संबंधित हैं। निर्विवाद रूप से, उन आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया था।

26. उत्तरदाताओं ने कुछ वैधानिक रजिस्ट्रों के रखरखाव और प्राप्तकर्ता इकाई में आवधिक रिटर्न दाखिल करने पर बहुत जोर दिया है, ताकि शुल्क की छूट के लिए पर्याप्त अनुपालन के सिद्धांत के तहत आश्रय लिया जा सके। उत्तरदाताओं ने बताया कि उनके पास प्राप्तकर्ता के छोर पर रखे गए रजिस्ट्रों में समान कॉलम थे, इसलिए, आपूर्तिकर्ता की ओर से रजिस्टर अलग बनाए रखने की आवश्यकता थी और अध्याय X की आवश्यकताओं का काफी हद तक पालन किया गया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्धारित आरजी-16 रजिस्टर अध्याय X के लिए विशिष्ट था, जिसका एकमात्र उद्देश्य आपूर्तिकर्ता इकाई से प्राप्त शुल्क मुक्त प्रेषित आदानों की प्राप्ति, जारी करने और उपयोग के लिए अलग-अलग खाते बनाए रखना था। कॉलम की समानता और उसमें दिए गए विवरण को आरजी-16 रजिस्टर या अध्याय X के तहत शुल्क की छूट के लिए अन्य रजिस्ट्रों को बनाए नहीं रखने के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है।

27. हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आपूर्तिकर्ता की ओर से नियम 174 के तहत कोई पंजीकरण प्राप्त नहीं किया गया था और न ही कोई अभिलेख रखा गया था। आवेदक, प्राप्तकर्ता की ओर से, कानूनी रूप से वैधानिक प्रपत्रों में विभिन्न घोषणाएं देने के लिए भी बाध्य थे ताकि छूट का दावा किया जा सके और ऐसी घोषणाएं स्वीकार्य रूप से नहीं की गईं। उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय X में विभिन्न नियमों के तहत उल्लिखित उन शर्तों का पालन न करना और अध्याय X के तहत निर्धारित विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों को प्रस्तुत न करना, हमारे विचार में, पर्याप्त अनुपालन और इच्छित उपयोग के अनुरोध के लिए घातक हैं। इसलिए, इस मामले के तथ्यों पर, उत्तरदाता "इच्छित उपयोग" या "पर्याप्त उपयोग" के अध्याय X में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन को स्थापित करने में सफल नहीं हुए हैं ताकि दिनांकित 11.8.1994 छूट अधिसूचना के लाभ का दावा किया जा सके।

28. अब हम जांच करेंगे कि क्या थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और जे. के. सिंथेटिक्स (ऊपर) के निर्णयों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में, निर्धारिती ने सीमा शुल्क के साथ-साथ अतिरिक्त शुल्क (सी. वी. डी.) का भुगतान करने के बाद आयातित वस्तुओं को मंजूरी दे दी थी। बाद में, यह महसूस किया गया कि उसे अधिसूचना एन. ओ. एस. के बल पर सी. वी. डी. के संबंध में रियायत का दावा करना चाहिए था। टैरिफ अधिनियम की धारा 8 के तहत जारी 63/85 और 93/76। इसलिए, सी. वी. डी. की वापसी के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे सहायक आयुक्त द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन अपील में आयुक्त द्वारा अनुमति दी गई थी। अपील पर, न्यायाधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया कि निर्धारिती अध्याय 10 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है। निर्धारिती द्वारा अपील पर, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटियां कर रहा था कि निर्धारिती को धनवापसी नहीं मिल सकती क्योंकि उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय 10 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस न्यायालय ने मुख्य रूप से बोर्ड के दिनांक

27.7.1987 के पत्र पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि जब भी आयातक द्वारा सामग्री का इच्छित उपयोग स्थापित किया जा सकता है, आयातित वस्तुओं पर छूट अधिसूचना के लाभ से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अध्याय 10 के तहत आने वाली प्रक्रियात्मक शर्त का पालन नहीं किया गया था। यह ऐसी परिस्थितियों में है कि इस न्यायालय ने निर्धारिती के दावे को स्वीकार कर लिया और धनवापसी का आदेश दिया। थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय का तर्क वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। इस मामले में, हम देश के बाहर से आयातित वस्तुओं से चिंतित नहीं हैं। निर्दिष्ट मध्यवर्ती वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ निर्दिष्ट अंतिम उत्पादों के निर्माता दोनों भारत में स्थित हैं और विभिन्न वैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, न केवल उत्पाद शुल्क की वस्तु के उत्पादन के लिए, बल्कि अधिसूचना दिनांक 11.8.1994 के तहत छूट का दावा करने के लिए भी। नतीजतन, सामग्री के इच्छित उपयोग का अनुरोध वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

29. जे. के. सिंथेटिक्स (ऊपर) में, निर्धारिती पॉलीस्टर चिप्स, स्टेपल फाइबर और मोनो-एथिलीन ग्लाइकोल (एम. ई. जी.) से टो का निर्माता था। उन वस्तुओं के आयात पर, उन्होंने उस पर सीमा शुल्क के अतिरिक्त भुगतान से छूट का दावा किया क्योंकि एम. ई. जी. को टैरिफ अधिनियम की धारा 8 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 4.5.1987 के आधार पर उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। उस मामले में, राजस्व द्वारा यह तर्क दिया गया था कि निर्धारिती ने उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय 10 में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया था। लेकिन न्यायाधिकरण ने तथ्यों पर पाया कि निर्धारिती द्वारा प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा कोई भी सिद्धांत निर्धारित किए बिना अनुमोदित किया गया था, जिसे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

30. नतीजतन, थर्मैक्स प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) और जे. के. सिंथेटिक्स (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णयों को सभी तथ्यों की स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता है और यह घोषित किया जाता है कि उन निर्णयों में दर्ज निष्कर्ष उन मामलों के तथ्यों तक ही सीमित होंगे।

सिविल अपील सं। 2001 का 1631

31. 2001 की सिविल अपील संख्या 1631 नई दिल्ली में न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 1.12.2000 आदेश से उत्पन्न होती है। उस मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट आबादी वाले मुद्रित सर्किट बोर्ड (पी. सी. बी.) को उपलब्ध थी, जिसे अधिसूचना सं.- 48/94-CE दिनांकित 1.3.1994 के तहत निर्धारिती द्वारा निर्मित और मंजूरी दी गई थी। न्यायाधिकरण ने पाया कि निर्धारिती अधिसूचना के लाभ के लिए पात्र नहीं था क्योंकि निर्धारिती ने अपनी इकाई से ए-11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण 1, नई दिल्ली में केंद्रीय स्टोर में पी. सी. बी. को मंजूरी देकर उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अध्याय 10 के तहत, जो निर्धारिती छूट अधिसूचना का लाभ उठाना चाहता था, उसे अधिकार क्षेत्र वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों को फॉर्म ए. एल.-6 में आवेदन दायर करना था और उसे एल.-6 लाइसेंस प्राप्त करना था और उस अध्याय में निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं का पालन करना था, जो हमारे विचार में, अन्य अपीलों में हमारे द्वारा चर्चा किए गए सिद्धांतों के आलोक में शुल्क से छूट का दावा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। तथ्यों के साथ-साथ कानून पर, हम न्यायाधिकरण द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और अपील खारिज हो जाएगी।

सिविल अपील संख्या- 2009 का 568-569

32. नई दिल्ली में न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 06.05.2008 के आदेश के खिलाफ राजस्व द्वारा इन अपीलों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती अधिसूचना संख्या- 3/2001-CE और 6/2001-CE के लाभ के हकदार हैं। इस तथ्य के बावजूद कि अध्याय 10 के तहत प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं। न्यायाधिकरण ने यह विचार व्यक्त किया कि अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन केवल प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा माल की प्राप्ति और उनके उपयोग को स्थापित करने के लिए किया जाना है।

33. इन अपीलों में निर्धारिती शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रमशः अध्याय 84 और अध्याय 73 के तहत आने वाले पंप पुर्जों और गन मेटल कास्टिंग के निर्माण में लगे हुए थे और उन्होंने उपरोक्त अधिसूचनाओं के लाभ का दावा किया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों ने 25.8.2004 को निर्धारिती के कारखाने परिसर में तलाशी ली। उस खोज के आधार पर, आयोग ने यह विचार लिया कि निर्धारिती ने छूट अधिसूचना की प्रक्रिया का उल्लंघन किया था और उत्पाद शुल्क योग्य माल को गुप्त रूप से हटा दिया था। निर्धारिती पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उसमें जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए, इसका कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद ने दिनांक 31.5.2007 के आदेश के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11-ए के प्रावधान के तहत मेसर्स नीटवेल कास्टिंग्स से दंड के साथ पांच साल की विस्तारित अवधि का आह्वान करके Rs.15,14,966/- के केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मांग की। निर्धारिती द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील में यह अभিনিर्धारित किया गया कि अधिसूचना के लाभ को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण ने अपील में आयुक्त (अपील) के फैसले को बरकरार रखा।

34. हमें न्यायाधिकरण के इस तर्क को बनाए रखना मुश्किल लगता है कि अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया, केवल प्राप्तकर्ता इकाई द्वारा माल की प्राप्ति और उनके उपयोग को स्थापित करने के लिए है। न्यायाधिकरण ने अध्याय 10 में निर्धारित प्रक्रिया के लक्ष्य और उद्देश्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। आपूर्तिकर्ता की ओर से निर्मित वस्तुएं उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं थीं और यदि कोई पक्ष शुल्क में छूट चाहता है, तो उसे कुछ पूर्व-आवश्यकताओं का पालन करना होगा, जिसका उद्देश्य यह देखना है कि छूट अधिसूचना की आड़ में माल को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट या उपयोग नहीं किया जाए। अध्याय 10 में विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं ताकि उन वस्तुओं के स्थानांतरण और दुरुपयोग पर अंकुश लगाया जा सके जो अन्यथा उत्पाद शुल्क योग्य हैं। इसलिए, "पर्याप्त अनुपालन" और "इच्छित उपयोग" की याचिका को पहले से बताए गए कारणों से खारिज कर दिया गया है।

35. नतीजतन, राजस्व द्वारा 2004 की सिविल अपील संख्या 1878-1880 और 2009 की सिविल अपील संख्या 568-569 को मंजूरी दी जाएगी और 2001 की सिविल अपील संख्या 1631 खारिज हो जाएगी। अर्थ दंड के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.जे

अपील का निपटारा किया गया।